संदेश

देशभर में साम्राज्यवाद-विरोधी, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद-विरोधी एवं सामंतवाद-विरोधी वर्ग संघर्ष को तेज करें!

जनाधार को बढ़ाते हुए, पार्टी और पीएलजीए को मजबूत करते हुए गुरिल्ला युद्ध को व्यापक और तेज करें!

भारत की क्रांतिकारी आंदोलन के उन्मूलन के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' रणनीतिक हमले को आत्मरक्षात्मक युद्ध के जरिए प्रतिरोध करें!

पीएलजीए की 19वीं वर्षगांठ को 2 से 8 दिसम्बर तक क्रांतिकारी उत्साह और दृढ़ता के साथ मनाएं!

पीएलजीए की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्रांतिकारी जन सरकारों, जनसंगठनों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं और जनता के लिए सेंट्रल मिलिटरि कमिशन (सीएमसी), भाकपा (माओवादी) का आह्वान!

सेंट्रल मिलिटरि कमिशन

भाकपा (माओवादी)

देशभर में साम्राज्यवाद-विरोधी, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद-विरोधी एवं सामंतवाद-विरोधी वर्ग संघर्ष को तेज करें!

जनाधार को बढ़ाते हुए, पार्टी और पीएलजीए को मजबूत करते हुए गुरिल्ला युद्ध को व्यापक और तेज करें!

भारत की क्रांतिकारी आंदोलन के उन्मूलन के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' रणनीतिक हमले को आत्मरक्षात्मक युद्ध के जरिए प्रतिररोध करें!

प्रिय कामरेडो और जनता!

2 दिसम्बर। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में हमेशा के लिए खड़े रहने का दिन है। हमारी पार्टी के संस्थापक द्वय, शिक्षकों, भारतीय क्रांति के निर्माताओं एवं अमर शहीदों कामरेड चारू मजुमदार और कामरेड कन्हाई चटर्जी के दिशानिर्देशन में, अमर शहीद कामरेड्स श्याम, महेश और मुरली की स्मृति में, हजारों अमर शहीदों के सपनों का साकार करने के लिए 2 दिसम्बर, 2000 को पीएलजीए का गठन हुआ। साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद एवं सामंतवाद के शोषण एवं उत्पीड़नों से हमारी देश को मुक्त कर अंत में समाजवाद एवं साम्यवाद की स्थापना करने के लक्ष्य से गठित हमारी वीर पीएलजीए को आगामी 2 दिसम्बर तक 19 वर्ष पूरा होंगे। इस अवसर पर समूची पार्टी के कमेटियों, कमांडों, पार्टी सदस्यों, पीएलजीए के कमांडरों एवं योद्धाओं, क्रांतिकारी जन सरकारों, जनसंगठनों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं, जनमिलिशिया के सदस्यों एवं क्रांतिकारी जनता को सेंट्रल मिलिटरि कमिशन (सीएमसी), भाकपा (माओवादी) क्रांतिकारी अभिवादन पेश करती है। पिछले

एक साल से प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' हमले को हराने के लिए राजनीतिक, सैनिक और सांगठनिक तौर पर किए गए प्रयास में भाग लेने वाले सभी कामरेडो का सीएमसी क्रांतिकारी अभिवादन पेश करती है। 'समाधान' हमले को हराने के लिए साहसिक हमलों का अंजाम देने के क्रम में एवं दुश्मन द्वारा हमारे बलों पर किए गए हमलों का साहसिक रूप से प्रतिरोध करते हुए नेतृत्वकारी कामरेडो को, पार्टी एवं पीएलजीए बलों को बचाते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर योद्धाओं को पिछले सालभर में घटित कई मुठभेड़ों में, फर्जी मुठभेड़ों में, धोखेबाजी हमलों, दुर्घटनाओं में, जेलों में, अस्वस्थता के वजह से और अन्य कारणों से अपने जान न्योछावर करने वाले सभी अमर शहीदों को सीएमसी विनम्रतापूर्वक क्रांतिकारी जोहार अर्पित करती है। आइए! उनके द्वारा पालन किए गए कम्युनिस्ट जीवन मूल्यों, दुश्मन के सामने न झुकने वाला उनका साहस, मृत्य से निडर वाले एवं कभी न थकने वाले उनका लड़ाकू शैली तथा जनता के प्रति उनके समर्पण को आदर्श के रूप में लेकर लागू करें! उनके लक्ष्य को हासिल करने और उनके सपनों को साकार करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ने की शपथ लें!

सीएमसी आशा करती है कि देशभर में चलायी गयी गुरिल्ला युद्ध कार्रवाइयों में घायल हुए सभी कामरेड शीघ्र ठीक होकर लड़ाकू जोश के साथ फिर से युद्ध मैदान में कूद पड़ेंगे।

2 से 8 दिसम्बर तक देशभर में हमारे आंदोलन के सभी इलाकों के गांवों और शहरों में पीएलजीए के 19वीं वर्षगांठ समारोह को क्रांतिकारी उत्साह और क्रांतिकारी दृढ़ता के साथ मनाने समूची पार्टी के कतारों, पीएलजीए के यूनिटों, क्रांतिकारी जन सरकारों, जनसंगठनों और क्रांतिकारी जनता को सीएमसी आह्वान करती है। दुश्मन द्वारा जारी प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' रणनीतिक हमले को हराने के लक्ष्य से पीएलजीए को संगठित करने हेतु देशभर में दिसम्बर महीनेभर में भर्ती अभियान चलाने का सीएमसी आह्वान करता है।

पीएलजीए वर्षगांठ मनाने का मतलब है पिछले सालभर में पीएलजीए द्वारा चलायी गयी राजनीतिक, सैनिक एवं सांगठनिक काम में सफलता एवं विफलताओं की समीक्षा करना, इस प्रयास में हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले अमर शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेना, दुश्मन द्वारा हमारे सामने रखे गये चुनौतियों का

स्वीकार कर उनका कारगर ढंग से कार्यनीति तय करना, क्रांतिकारी आंदोलन के सामने खड़ी समस्याओं को पहचान कर उनको हल करने के लिए उचित संघर्ष एवं सांगठनिक रूपों एवं कार्यपद्धतियों को तय करना, तय कर्तव्यों का अमल करने के लिए माओवादी लड़ाकू शैली के साथ आगे बढ़ने का शपथ लेना। इसे ध्यान में रखकर पीएलजीए के 19वीं वर्षगांठ मनायेंगे।

भारत की नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने के लक्ष्य से, एकता कांग्रेस-9वीं कांग्रेस द्वारा निर्देशित कर्तव्यों को हासिल करने का प्रयास करते हुए एवं 'समाधन' हमले को हराने के लिए लड़ते हुए पिछले 10 महीनों में (दिसम्बर 2018 से सितम्बर 2019 तक) देशभर में 128 कामरेड शहीद हुए। दण्डकारण्य (डीके) में ताडबल्ला, गुममरका; बिहार-झारखण्ड (बीजे) व पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखण्ड (पू.बि.-पू.उ.झा) में बरी, डुमरीनाला, सतनदिया; आंध्र-ओड़िशा सीमा (एओबी) इलाके के कितुबा, माचकोट, गुम्मुरेवुला; महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (एमएमसी) में सीतागुट्टा; ओड़िशा में मैनपुर इलाके के कट्टीगांव एवं मांदगिरी घटनाओं में हमें गंभीर नुकसान उठाना पड़ा। खास तौर पर हमारे कार्यनीतिक जवाबी-हमले का अभियान (टीसीओसी) खत्म होने के बाद हमारे बल विकेंद्रीकृत होकर जनकार्य (मासवर्क) में जाने के बाद जून से सितम्बर तक हमें ओड़िशा, एओबी, एमएमसी एवं डीके में अधिक नुकसान हुए। ये सब गुप्त कामकाज एवं गुरिल्ला युद्ध नियमों का पालन करने में जारी कमी-कमजोरियों को न सुधारने की वजह से ही हुए। इसके अलावा अन्यान्य मुठभेड़ों एवं फर्जी मुठभेड़ों में कई कामरेड शहीद हुए। कुल मिलाकर देखें तो, दण्डकारण्य के 78 कामरेड, बिहार-झारखण्ड व पूर्वी बिहार-पूर्वोत्तर झारखण्ड के 16 कामरेड, ओड़िशा के 11 कामरेड, आंध्र-ओड़िशा सीमा इलाके के 14 कामरेड, तेलंगाना के एक कामरेड, एमएमसी सीमा इलाके के 8 कामरेड इस अवधि में शहीद हुए। इनमें से 36 महिला कामरेड शामिल हैं।

इस सालभर में शहीद कामरेडो में जोनल/डिविजिनल/जिला कमेटी/सीवाइपीसी के सदस्य पांच कामरेड; एसी/पीपीसी सदस्य 25 कामरेड; पार्टी व पीएलजीए (प्रधान एवं द्वितीय बलों) के सदस्य 67 कामरेड, क्रांतिकारी जन सरकारों (आरपीसी) एवं जनसंगठन के नेता व कार्यकर्ता 7 कामरेड, मिलिशिया कमांडर व सदस्य 13 कामरेड, क्रांतिकारी जनता 11 कामरेड शामिल हैं।

प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' को हराने के लिए देशभर में हमारे द्वारा चलाये गये राजनीतिक, सैनिक और सांगठनिक कार्य-उसके परिणाम

दिसम्बर 2018 से सितम्बर 2019 तक बीते 10 महीनों में हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए ने विभिन्न गुरिल्ला जोनों और लालप्रतिरोध इलाकों में लगभग 360 गुरिल्ला कार्रवाइयों को अंजाम दिए। पीएलजीए ने सीधा दुश्मन के बलों पर लगभग 70 कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इसमें कुछ बड़ी कार्रवाइयां शामिल है, बाकी अधिकतर छोटे एवं मध्यम किस्म के कार्रवाई है। लगभग 130 मुठभेड़ों में पुलिस-अर्धसैनिक बल-कमांडो बलों के साथ पीएलजीए बलों ने लोहा लिए।

दण्डकारण्य में नवम्बर 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बहिष्कार के समय में संचालित टीसीओसी के साथ इस साल जनवरी से जून तक चलाये गये टीसीओसी के तहत गुरिल्ला युद्ध कार्रवाइयों में 75 पुलिस, अर्धसैनिक एवं कमांडो मारे गए और 147 घायल हो गए तथा 13 हथियार जब्त किये गये। दण्डकारण्य में हुई गुरिल्ला युद्ध कार्रवाइयों में दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी के साथ पांच पुलिस वालों का सफाया, उत्तर गढ़चिरोली के जांबुरखेड़ा के पास सी-60 के 15 कमांडो पुलिस का सफाया करने वाला साहसिक एम्बुश, उत्तर बस्तर के महला के पास बीएसएफ के चार जवानों का सफाया एवं 15 जवानों को घायल करना, पश्चिम बस्तर के मुरदोण्डा के पास एमपीव्ही गाड़ी को विस्फोट से उड़ा देने वाली घटना, केशकुतुल एम्बुश जैसे बढ़े कार्रवाई थे, बाकी छोटे एवं मध्यम किस्म की कार्रवाई।

इस वर्ष बिहार-झारखण्ड स्पेशल एरिया में हमारे पीएलजीए के गुरिल्ला बलों द्वारा मई-जून महीनों में चलाये गये कार्यनीतिक जवाबी-हमले के अभियान (टीसीओसी) सफल रही। इसमें दुमका जिले एवं सारंडा इलाके के सराईकेला-खरसवां जिले में दुमका, तिरडीह जैसे एम्बुशों में लगभग 10 पुलिस वालों का सफाया हुआ एवं 32 पुलिस घायल हुए। बहुत दिन के बाद दुमका एवं सारंडा आदि इलाकों में फिर से टीसीओसी चलाकर सफल करना क्रांतिकारी कतारों एवं जनता के अंदर उत्साह पैदा किया।

एओबी में गुरिल्ला बलों ने कुछ छोटे कार्रवाई, ध्वस्त कार्रवाई संचालित करने के अलावा कुछ मुखबिरों का सफाया किया।

ओड़िशा में सीमित संख्या एवं कई सीमितताएं होने के बावजूद दुश्मन के सशस्त्र बलों कुछ एम्बुश/युद्ध कार्रवाइयों को अंजाम देना अच्छा परिणाम है।

तेलंगाना एवं डीके के गुरिल्ला बल मिलकर सीमा इलाके में संयुक्त ऑपरेशन में भाग लेकर दुश्मन के हमले को रोकने के लिए प्रयास किये। डीके में सफल कुछ सशस्त्र कार्रवाइयों में तेलंगाना बल शामिल हुए।

देशभर में आंदोलन के इलाकों में पिछले 10 महीनों में संचालित गुरिल्ला युद्ध कार्रवाइयों में खास बात यह है कि इसमें अधिकतर दुश्मन के कार्पेट सुरक्षा वाले इलाकों की ही थीं। इसी तरह इन घटनाओं में सफाया किये गये पुलिस वालों में अधिकतर अर्धसैनिक एवं कमांडो बलों के ही थे।

इस वर्ष अप्रैल-मई महीनों में हमारी पार्टी ने संसदीय चुनाव बहिष्कार अभियान को देशभर में लालप्रतिरोध इलाकों एवं गुरिल्ला जोनों में व्यापक रूप से संचालित किया। झूठी संसदीय व्यवस्था का एकमात्र विकल्प नवजनवादी गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना ही है के संदेश एवं क्रांतिकारी जन सरकारों (आरपीसी) के वैकल्पिक कार्यक्रम को जनता में ले गयी थी। डीके में कई आरपीसीयों ने पूरी तरह संसदीय चुनावों का बहिष्कार की। इसके अलावा सैकड़ों गांवों में हुई मतदान सिर्फ नाममात्र ही थी। आंदोलन के इलाकों में इस चुनाव बहिष्कार एक व्यापक राजनीतिक व सैनिक अभियान के रूप में संचालित किया गया। इससे दुश्मन सैकड़ों मतदान केंद्रों को 'सुरक्षित' इलाकों में स्थानांतरित करना पड़ा। देश में हमारी आंदोलन के इलाकों में लाखों पुलिस, अर्धसैनिक एवं कमांडो बलों को तैनात कर दुश्मन द्वारा संचालित इन चुनावों ने उसके प्रति जनता अनासक्ति, चुनाव की फर्जीवाड़ा एवं खोखलेपन का उजागर किये।

इस अवधि में आंदोलन के इलाकों में लगभग 94 कार्रवाइयों को संचालित कर 75 जन दुश्मन मुखबिरों, शोषणकारी राजनेताओं, प्रतिक्रांतिकारी तत्वों एंव गद्दारों को हमारे पीएलजीए के प्रधान, द्वितीय एवं बुनियादी बल तथा जनता ने मिलकर सफाया किये।

देशभर क्रांतिकारी आंदोलन के कठिन दौर से उबरने एवं 'समाधान' हमले को हराने के लिए हमारे आंदोलन जारी विभिन्न स्पेशल एरिया/स्पेशल जोन/राज्यों में हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए बलों, क्रांतिकारी जन निर्माणों एवं जनता विभिन्न स्तरों में गुरिल्ला युद्ध चला रहे हैं। इस साल भर में हमने विभिन्न स्पेशल एरिया/स्पेशल जोन/राज्यों में अपेक्षाकृत मजबूत होने के लिए प्रयास किये। देश के विभिन्न जंगल इलाकों में जल-जंगल-जमीन-इज्जत-अधिकार के लिए साम्राज्यवाद-विरोधी, दलाल नौकरशाह पूंजवाद-विरोधी एवं सामंतवाद-विरोधी

संघर्ष जारी है। देश का विकास के नाम पर देश के विभिन्न इलाकों में विभिन्न किस्म के प्राकृतिक संपदाओं को लूटने एवं आंदोलन को कुचलने के लिए केंद्र व राज्य पुलिस बलों की तैनाती कर माइनिंग एवं बुनियादी सुविधा वाले प्राजेक्टों को रोकने के तहत पीएलजीए बलों ने व्यापक रूप से जनता को गोलबंद कर 65 गुरिल्ला कार्रवाइयों में करोड़ों रूपयों के दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों एवं सरकार के संपत्ति को ध्वस्त किये। दण्डकारण्य के किरंदूल-बैलाडिला पहाड़ श्रृखला में 11बी डिपाजिट को केंद्र व राज्य सरकारें भारतीय बड़े कार्पोरेट कंपनी अदानी को किराये पर देने का विरोध करते हुए एवं नंदराज पहाड़ को बचाने का नारे को लेकर जनता लड़ रहे हैं। आंदोलन के सभी इलाकों में धक्के खाये हुए जन निर्माणों का पुनरनिर्माण-मजबूतीकरण जारी है। दण्डकारण्य में पितृसत्ता-विरोधी अभियान, बीजे व पू.बी.-पू.उ.झा. में, ओड़िशा एवं एमएमसी में बोल्शेवीकरण अभियान, तेलंगाना में जनसंगठनों का शुद्धीकरण अभियान जारी है। देशभर में पार्टी का मजबूतीकरण (consolidation) अभियान शुरू हुआ। मध्य रीजिनल ब्यूरो इलाके में पीएलजीए के बलों में कंबैट स्किल्स-टेकनिकल स्किल्स बढ़ाने के लिए कई विषयों पर प्रशिक्षण चलाये जा रहे हैं। स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक देशभर में विभिन्न रूपों में ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद-विरोधी संयुक्त आंदोलनों का निर्माण शुरू हुआ।

देशभर में सभी स्तरों में हमारी पार्टी कमेटियां वर्तमान राजीतिक परिस्थितियों में व्यापक जनता को गोलबंद करने में सहयोग करने वाले कार्यक्रमों को तय कर जुझारूपन, धैर्य एवं साहस के साथ आंदोलनों का नेतृत्व प्रदान करने प्रयासरत हैं। वर्गसंघर्ष को जारी रखते हुए, जनाधार को बढ़ाते हुए पार्टी व पीएलजीए को मजबूत करते हुए गुरिल्ला युद्ध को व्यापक व तेज करने के लिए सभी स्तरों के पार्टी कमेटियों, यूनिटों, पीएलजीए कमांडों, यूनिटों, क्रांतिकारी जनसत्ता के इकाइयों, जन संगठनों - सभी ने एकजुटा से कार्य कर रहे हैं। यह तमाम काम वर्तमान में प्राथमिक रूप से होने के बावजूद तीन जादुई हथियार - पार्टी, पीएलजीए एवं संयुक्तमोर्चा ने एकजुटता से अपने प्रयास जारी रख पाने से, इन कामों में जो भी सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, कठिन दौर से उबरने के लिए नींव रखेंगे। इस प्रयास में अनुभवों को संश्लेषण करते हुए सकारात्मक पहलुओं पर आधारित होकर, नकारात्मक पहलुओं से बचते हुए सफलताओं को जनता एवं कतारों में प्रचारित-प्रसारित करते हुए तथा उन सफलताओं को बचाते हुए आगे बढ़ेंगे।

प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' हमले को हराने के लिए साम्राज्यवाद-विरोधी, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद-विरोधी और सामंतवाद-विरोधी वर्गसंघर्ष को तेज करें। इस वर्गसंघर्ष के जरिए जनाधार को बढ़ाते हुए, पार्टी और पीएलजीए को मजबूत करते हुए गुरिल्ला युद्ध को व्यापक और तेज करें।

मई 2017 में शुरू की गयी 'समाधान' हमले केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद और तेज हो गयी है। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभावित राज्यों में सत्ता में भाजपा हो, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय पार्टियां - वाइएसआर सीपी, बिजू जनतादल एव टीएमसी - जो भी हो केंद्र व राज्य सरकारें समन्वय के साथ 'समाधान' हमले तेज रूप से ही संचालित किया जा रहा है।

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद 26 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में माओवादी आंदोलन से प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में यूपीए के शासन में (2009-13) माओवादी आंदोलन की तीव्रता एवं एनडीए-1 के शासन में (2014-18) माओवादी आंदोलन की तीव्रता को तुलना कर विश्लेषण कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। इस समीक्षा के आधार पर यह आकलन किया गया कि 2018 अंत तक 'वामपंथ उग्रवाद' देशभर में 10 राज्यों में 60 जिलों तक ही सीमित रह गयी है, उसमें से दो तिहाई घटानाएं 10 जिलों में ही हो रहे हैं। इसी तरह आकलन किया गया कि इस वर्ष पहले पांच महीनों में 310 माओवादी संबंधित घटनाएं घटित थीं।

इस समीक्षा पर एवं आकलन पर आधारित होकर आगामी तीन सालों में 'नक्सल-विहीन नवभारत' का निर्माण करने की 'कार्ययोजना' को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषित किया। मई 2017 में बनायी गयी 'समाधान' रणनीतिक हमले के तहत ही 26 अगस्त की उक्त दिल्ली बैठक अपनी कार्ययोजना (एक्शन प्लान) बनायी। इसके तहत ही उस बैठक ने निम्नलिखित पहलुओं के साथ एक खुला (ओवर्ट) 'कार्ययोजना' बनायी कि माओवादियों को पैसे का पहुंच बंद करना; शहरी नेटवर्क के नाम पर जनसंगठन के नेतृत्व पर देशद्रोह के मामले में आपराधिक केस थोप कर जेल में डालना; क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभावित इलाकों में और अधिक सड़क एवं सेल टॉवर बनाना; सड़कों के निर्माण में स्थानीय युवा को ही प्राथमिकता देना; सेल टॉवरों के निर्माण में निजी कंपनियों को प्राथमिकता देना; सरकारों की नगद बदली योजनाओं से माओवादी

प्रभावित इलाकों के जनता एवं आदिवासियों द्वारा आसानी से लाभ उठाने के लिए अधिक बैंकों, एटीएम और डाकघरों को स्थापित करना; 'एकलव्य' नमूना में पाठशालाएं स्थापित करना; आंदोलन के प्रभावित राज्यों में अर्धसैनिक बलों को बढ़ाना; दण्डकारण्य के माड क्षेत्र को नाकेबंदी करने के लिए अर्धसैनिक बलों के सात बटालियनों का आंबटन आदि। इस के तहत ही बहुत ही गुप्त (कोवर्ट) फासीवादी दमन कार्रवाइयों से संबंधित कार्यक्रमों को भी तैयार की गयी।

केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से बनायी गयी इस योजना के साथ विभिन्न राज्य सरकारें और कुछ योजनाएं बनायीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने माड के स्थानीय लोगों को आवास जमीन पट्टे देने की कपटपूर्ण योजनाएं घोषणा की। तेलंगाना सरकार ने एक ही समय में 18 हजार पुलिस वालों को भर्ती कर क्रांतिकारी आंदोलन फिर से न उबरा जाय – इसके लिए पुलिस भर्ती को घोषणा की। उसने माओवादियों को कुचलने के लिए छः बटालियनों के अर्धसैनिक बलों को मांग कर रही है। सितम्बर में विशाखा जिला के सीलेरु इलाके में पांच माओवादियों को मुठभेड़ के नाम पर हत्या करने वाली वाइएसआर कांग्रेस सरकार ने अपनी व्यवहार द्वारा बताया कि माओवादियों को दमन करने में केंद्र सरकार की तरह सख्त रवैया अपनायेगी। बिहार–झारखण्ड राज्यों में भी बंदूक का राज्य चल रहा है। इसी तरह बाकी राज्य सरकारें भी क्रांतिकारी आंदोलन का दमन के लिए केंद्र द्वारा बनायी गयी 'समाधान' हमले की योजना को अमल करने के लिए और कुछ स्थानीय योजनाएं बनायीं।

केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनायी गयी इन योजनाओं का यही सार है कि आगामी तीन सालों में 'माओवादी–रहित फासीवादी भारत' का निर्माण करना। यानी देश में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवादी व सामंतवादी शोषण व उत्पीड़नों को स्थायी बनाना एवं उत्पीड़ित जनता से उक्त वर्गों के शोषण के लिए किसी भी तरह का रुकावट को हटाना ही है। माओवादी आंदोलन के दमन के नाम पर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा का ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी राज्य को स्थापित करने के लिए और आक्रामक रुख अपना रही है। 'माओवादी–रहित नवभारत' निर्माण करना केंद्र व राज्य सरकारों के लिए उतना आसान नहीं है, जितना वे सोच रही हैं। 'माओवादी–रहित भारत', ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी राज्य की स्थापना के लक्ष्य है – व्यापक आम जनता के मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, छोटे व मध्यम स्तर के पूंजीपतियों के हितों, उत्पीड़ित सामाजिक समुदायों –

महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के हितों का सख्त खिलाफ है। इसलिए उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित सामाजिक समुदायों एवं उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं ने अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हितों को बचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अपनायी जा रही देशद्रोही व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रही हैं। आगामी दिनों में इन आंदोलन और तेज होंगे। इस स्थिति में व्यापक जनता को गोलबंद कर वर्ग संघर्ष को तेज करते हुए, जनाधार को बढ़ाकर, पार्टी व पीएलजीए को मजबूत करते हुए गुरिल्ला युद्ध को व्यापक-तेज करने द्वारा ही 'समाधान' हमले को प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने के अलावा अंत में उसे हरा सकते हैं। इसके लिए आगामी समय में निम्नलिखित राजनीतिक, सैनिक एवं सांगठनिक कर्तव्य को लेकर काम करेंगे:

हमारी पार्टी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारी केंद्रीय कमेटी द्वारा समूचे पार्टी के सामने पार्टी की मजबूतीकरण का जो कार्य रखी गयी है, उसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए।

देशभर में समूचे आंदोलन के इलाकों में साम्राज्यवाद-विरोधी, बड़े पूंजीपति-विरोधी एवं सामंत-विरोधी वर्गसंघर्षों एवं सामाजिक आंदोलनों को तेज करना चाहिए। आंदोलन के इलाकों के शहरी, मैदानी एवं जंगली इलाकों में जनता के दैनिंदिन व मौलिक समस्याओं पर आंदोलन चलाना चाहिए। जनांदोलन/ वर्गसंघर्ष ही नयी शक्तियों को गोलबंद करने का स्रोत है - इस समझ के साथ जहां जनता आंदोलनों में गोलबंद हो रहे हैं, वहां पेशेवर क्रांतिकारियों एवं संगठनकर्ताओं को भेज कर नये संघर्ष क्षेत्रों को विकसित करना होगा। पेशेवर क्रांतिकारी एवं संगठनकर्ता 'बीजों' के तरह काम करते हुए जनांदोलनों के पुरोगामी शक्तियों से पेशेवर क्रांतिकारियों को तैयार करना चाहिए। शहरी एवं मैदानी इलाकों में सिर्फ आम प्रचार-प्रसार एवं आंदोलनों तक सीमित न रहकर जुझारू आंदोलन चलाते हुए नयी शक्तियों के साथ अत्यंत गुप्त तरीकों में पार्टी को निर्माण करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नयी शक्तियों से विकसित हुई पार्टी शक्तियों द्वारा ही नयी पार्टी कमेटियों को निर्माण करना चाहिए।

केंद्र में भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आने के कारण ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी तत्वों के अत्याचार बेरोकटोक जारी है। गोरक्षकों के नाम पर हमला करने के अलावा जय श्रीराम नारे के साथ देशभर में दलितों, आदिवासियों,

धार्मिक अल्पसंख्यकों पर किये जा रहे हमले, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। आगामी दिनों में ये हमले और तेज होंगे। इस स्थिति में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ एक तरफ वैचारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में दीर्घकालीन योजना के साथ उचित निर्माण गठित कर संघर्ष करते हुए दूसरी तरफ हिंदुत्व फासीवादियों को मार भगाओ, देश को बचाओ का नारा के साथ जुझारू प्रतिरोध हमले कर ब्राह्मणीय हिंदू फासीवादी तत्वों को मार भगाना चाहिए। इन जुझारू प्रतिरोध हमले न सिर्फ उत्पीड़ित जनता की रक्षा करने का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि देशभर में पार्टी विस्तार करने का स्रोत की भूमिका भी अदा करते हैं।

ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद-विरोधी संघर्ष को साम्राज्यवाद-विरोधी, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद-विरोधी, सामंत-विरोधी वर्गसंघर्ष में अभिन्न अंग के रूप में आज एक मुख्य राजनीतिक कर्तव्य के रूप में पहचान कर उसे जुझारू रूप से संचालित करना चाहिए। आंदोलन के इलाकों में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी संगठनों (आरएसएस, भाजपा, एबीवीपी, भाजयुमो, भजरंगदल, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम आदि) के विस्तार को रोकना चाहिए। इस विस्तार को रोकने के लिए वैचारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में दीर्घकालीन योजना के साथ प्रयास करने के लिए जरूरी संघर्ष एवं सांगठनिक तरीके अपनाना चाहिए। संघ परिवार की विचारधारा जिस तरह से उत्पीड़ित वर्गों, उत्पीड़ित सामाजिक समुदायों - महिला, दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं प्रजातंत्र के लिए कट्टर दुश्मन है - इसे लगातार विभिन्न रूपों में भण्डाफोड़ करने की तरह कानूनी एवं खुला संघर्ष एवं सांगठनिक रूपों को इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ जुझारू जनप्रतिरोध आंदोलनों को चलाते हुए उसका विस्तार को रोकना चाहिए। ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ स्थानीय स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक व्यापक बुनियाद पर मित्रशक्तियों के साथ एकजुट होना चाहिए। इस पहलू में किसी भी संकीर्ण रवैये को देर किये बिना सुधारना चाहिए।

विभिन्न इलाकों के उत्पीड़ित जनता के लड़ाकू तैयारी के बुनियाद पर उन्हें कानूनी एवं गैरकानूनी; खुले-गुप्त संघर्ष एवं सांगठनिक रूपों में गोलबंद कर संगठित करना चाहिए।

जैसाकि पहले बताया गया, साम्राज्यवाद-विरोधी, दलाल नौकरशाह-विरोधी, सामंत-विरोधी वर्गसंघर्षों में व्यापक जनता को गोलबंद कर, उसमें शामिल सक्रिय एवं जुझारू शक्तियों को हमारे जनसंगठनों एवं अन्य संगठनों में संगठित

कर हमारे जनाधार को मजबूत करना चाहिए। इस जनाधार के बुनियाद पर पार्टी एवं पीएलजीए को मजबूत करना चाहिए।

वर्गसंघर्ष में आगे आने वाली शक्तियों के साथ पार्टी एवं पीएलजीए को मजबूत करते हुए दुश्मन के हमलों से हमारे नेतृत्व को एवं बलों को बचाते हुए देशभर में लाल प्रतिरोध इलाकों एवं गुरिल्ला जोनों में हमारे ताकत के मुताबिक गुरिल्ला युद्ध को व्यापक व तेज करना चाहिए। दुश्मन के 'समाधान' हमलों के बीच ही, उसे प्रतिरोध करने के लिए टीसीओसीयां संचालित करते हुए ही भर्ती अभियानों को सफल बनाकर पीएलजीए को मजबूत करना चाहिए।

जनाधार, टेरेन की अनुकूलता एवं पीएलजीए के फारमेशनों के स्तर के बुनियाद पर मौके पाकर एवं उन मौकों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हुए छोटे, मध्यम एवं बड़े किस्म की कार्रवाइयों के जरिए सशस्त्र दुश्मन को यथासंभव अधिक मात्रा में सफाया कर हथियार-गोलाबारूद जब्त करना चाहिए।

कार्पेट सुरक्षा के इलाकों में भी जन राजसत्ता को लागू करने में हमें मिल रहे नये अनुभवों के आधार पर क्रांतिकारी जन कमेटियों/जनताना सरकारों द्वारा सक्रिय रूप से कार्य चलाना चाहिए।

केंद्रीय मिलिटरि कमिशन का आह्वान:

अंतरराष्ट्रीय एवं देशीय स्तर पर मौलिक अंतरविरोध तेज होने के फलस्वरूप क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बढ़ रही हैं।

पूंजीवादी/साम्राज्यवादी व्यवस्था में पहले के मुकाबले पिछले साल गंभीर स्तर पर अमेरिकी-चीनी साम्राज्यवादी देशों के बीच बढ़ी वाणिज्यक युद्ध अभी भी जारी है। इस साल जून में जापान में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग मिलकर दोनों तरफ से बढ़ाई गयी वाणिज्यक शुल्क वापस लेने पर वार्ता करने एवं उचित कदम उठाने का निर्णय लेने के बावजूद इस वाणिज्यक युद्ध तीव्र रूप से जारी है। वाणिज्यक एवं मुद्रा संबंधी युद्धों से तेज हुए अमेरिकी-चीनी अंतरविरोधों ने अब सामरिक क्षेत्र में भी विस्तारित हुए। चीन एवं रूस के खिलाफ अमेरिका द्वारा अपनायी जा रही नीतियां इन देशों के बीच बढ़ती सैनिक शत्रुता को दर्शाती हैं। इसी बीच रूस से मध्यमश्रेणी परमाणु मिसाइलों (आइएनएफ-इंटरमीडियट

रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी) का समझौता को अमेरिका ने एकतरफा खत्म किया। इस समझौते के मुताबिक अमेरिका एवं रूस 500 से 5,000 किलोमीटर के दायरे में अपने लक्ष्यों पर हमला कर सकने वाली मध्यमश्रेणी के मिसाइलों को सीमित रखना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने चीन पर लंबेश्रेणी मिसाइलों की तैयारी की, रूस भी यथेष्ट उक्त समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर आइएनएफ समझौते से खुद को अलग कर दिया। अपने परमाणु मिसाइलों को रूस एवं चीन के सीमाओं पर तैनात करने की तैयारी कर रही है। उनसे चीन को नियंत्रित करने के लिए दक्षिणी कोरिया में थाड मिसाइल प्रणाली को पहले ही तैनाती की है। अमेरिका ने जापान एवं आस्ट्रेलिया से मिलकर सैनिक विन्यास चलायी है। उसने चीन के खिलाफ ताइवान एवं हांग कांग में हो रहे दंगों को बहकाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा विगत में 80 की दशक में अमेरिका एवं रूस के बीच हुई न्यूस्टार्ट (नयी रणनीतिक हथियार कम करने का समझौता) समझौता की समयावधि 2021 तक खत्म होने जा रही ही है। इस अवधि को बढ़ाने पर अमेरिका तैयार नहीं है। चीन अपनी रक्षा श्वेतपत्र में चेतावनी दे चुकी है कि अमेरिका, जापान एवं आस्ट्रेलिया के आक्रामकता का कारगर ढंग से मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ अभी तक उग्रवाद पर संघर्ष का प्राथमिकता देने वाली अमेरिका, अब अपने रणनीतिक एवं आर्थिक हितों के लिए चीन एवं रूस के साथ प्रतिस्पर्धा लेने, जरूरत पड़े तो संघर्ष में उतरने का निर्णय लिया है।

यूरोपीय संघ (ईयू) के देशों में पूंजीपति वर्ग एवं मजदूर वर्ग के बीच अंतरविरोध तेज होने के कारण वहां जनांदोलन तेज हो रहे हैं। ईयू के लगभग सभी देशों में सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं एवं सुरक्षा को कमजोर करते हुए मजदूरों के अधिकारों का हनन करने का कानूनों के खिलाफ मजदूर वर्ग एवं मध्यम वर्ग आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच जर्मनी, पुर्तुगाल एवं बेल्जियम में न्यूनतम वेतन के लिए हड़ताले हुईं। फ्रांस में 'पीले जाकेट' आंदोलनकारियों का आंदोलन जारी है। इसके अलावा पेट्रोल दर कम करने के लिए हड़तालें हुईं। पोलैंड में शिक्षकों ने अपनी समस्याओं का हल के लिए हड़ताल किये। हंगेरी में ओवरटाइम काम का भुकतान के लिए हड़ताल हुई।

पश्चिमी एशिया में साउदी अरेबिया पर आधारित होकर और एक बार युद्ध सुलगाने के लिए अमेरिका दुस्साहस कर रही है। जेरूसलेम को इज्रायल

राजधानी के रूप में उसके द्वारा मान्यता देने के बाद फिलिस्तीन पर इस्रायल हमला और तेज हो गयी। उसने सिरिया में गृहयुद्ध को कभी न भुजाने वाली आग की तरह सुलगाती रही है, लेबनान एवं इरान में गृहयुद्ध बहकाने की तीव्र कोशिशें कर रही है। वेनेजुवेला में शासक वर्गों के बीच संघर्ष को बहाना बनाकर अमेरिका की हस्तक्षेप नीति, रूस व चीन के सैन्य बल उस देश में पैठ बनाकर रखने की वजह से वहां गृहयुद्ध की खतरा बढ़ गयी है। हाल ही में इस वर्ष (2019) मई में यूरोपीय संघ के कई प्रमुख देश विरोध करने के बावजूद इरान के साथ परमाणु समझौते को ट्रंप ने एकतरफा खत्म करने की घोषणा किया। इस समझौते को खत्म करने की घोषणा के तुरंत बाद इरान पर तीव्र आर्थिक प्रतिबंध लगायी है। उसे नाकेबंदी करने के लिए अमेरिकी युद्धपोत को होरमुज जलसंधि में तनात की। इरान से परमाणु समझौते से खत्मकर उसकी तेल निर्यातों पर अमेरिका द्वारा लगायी गयी प्रतिबंधों की वजह से विश्व तेल बाजार उथल-पुथल हो रहा है। चीन के साथ अमेरिकी वाणिज्यक युद्ध ने विश्व बाजार को हिलाकर रखा है। इससे 2008 में शुरू होकर जारी विश्व आर्थिक संकट और तेज होना का आसार है। इस आर्थिक संकट की तीव्रता के साथ विश्वभर में - अमेरिका, यूरोप सहित पिछड़े हुए देशों में भी नस्लवादी रुझानें, फासीवादी रुझानें बढ़ रहे हैं। ये सब ऐसे परिस्थितियों की तरफ विश्वभर में उत्पीड़ित वर्गों - मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग एवं राष्ट्रीय पूंजीपतियों - को धकेल रहा है कि अनिवार्य रूप से लड़ें। उत्पीड़ित राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलनों तहत अफगानिस्तान में तालिबनों का संघर्ष, येमेन में हूती भगावत, कुर्द राष्ट्रीय-मुक्ति संघर्ष आदि ने और जुझारू रूप ले रहे हैं। इसी तरह विश्वभर में विभिन्न देशों उत्पीड़ित सामाजिक समुदायों - अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, रोजगार के लिए एवं युद्धग्रस्त देशों से पलायन कर गये मजदूरों-कर्मचारियों, महिलाओं, आदिवासियों/मूलवासियों आदि पर वर्ग शोषण सहित सामाजिक उत्पीड़न एवं हिंसा तीव्र हो जाने की वजह से वे तबके लड़ने में मजबूत होने की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं।

देशीय परिस्थिति को अगर देखा जाय, तो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार मई महीना में दूसरी बार सत्ता में आने के तुरंत बाद 2022 तक ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी राज्य की स्थापना करने के एजेंडे को तेजी से अमल में लाने के लिए आक्रामक रूप से प्रयास कर रही है। अपनी सरकार के अत्याचार एवं भ्रष्टाचार

के बारे में जनता को पता न चले – इसके लिए सूचना अधिकार कानून को कमजोर करने की संशोधन किया। राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार संगठनों को कमजोर करने मानवाधिकार कानून में संशोधन किया। जनता पर एवं भिन्नमत होने वालों पर ढहने के लिए, अपने प्रतिद्वंद्वियों को, माओवादियों के नाम पर जनांदोलन के कार्यकर्ताओं को अवैध मामलो में फंसाने के लिए, घोर सजाएं देने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के अधिकार बढ़ाते हुए एनआइए कानून में संशोधन किया। व्यक्तियों को भी उग्रवादी घोषित करने एवं देश के दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, मानवाधिकार कायकर्ताओं, माओवादियों को उग्रवादी के रूप में घोषित करने के प्रावधान शामिल कर गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (उपा) में संशोधन किया। ये सभी कानूनी संशोधन अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर, भिन्नमत रखने वालों पर, संघ परिवार के विरोधियों पर, कुल मिलाकर प्रगतिशील, जनवादी एवं क्रांतिकारी शक्तियों पर दमन और फासीवादी तरीकों में तेज करने की रणनीति के तहत ही लाया गया है।

अभी तक गोरक्षा के नाम पर दलितों, आदिवासियों एवं मुस्लिमों पर हमले करने वाले हिंदू फासीवादी अभी जय श्रीराम का नारा लगाने पर मजबूर करते हुए हमले तेज की हैं। जर्मनी में हिट्लर के फासीवादी नाजी तत्वों ने जिस तरह यहूदियों पर हमले कर कत्ल किये उसी तरह पिछले पांच सालों से उत्पीड़ित जनता पर हुयी फासीवादी हमले और तेज होने की आसार है।

मध्यम वर्ग, बेरोजगारी युवाओं एवं छात्र व युवाओं को भ्रम में डालने के लिए मोदी सरकार ढिंढोरा पीट रहा है कि 2024 तक देश को पांच ट्रिलियन (50 खरब) डालर अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करेंगे एवं उसके जरिए देश को एक विकसित देश के रूप में तब्दील करेंगे, तब देश में गरीबी हटेगी। दरअसल देश में नोटबंदी एवं जीएसटी ने असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ दी। केंद्र व राज्य सरकारें 1991 से अपनायी गयी नीतियों के दुष्परिणामों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था–कृषि क्षेत्र का विनाश हो गयी। इसके अलावा विश्व आर्थिक संकट के प्रभाव भी शामिल होकर देश के जनता की क्रयशक्ति कम हो गयी एवं सभी तरह के चीजों के बिक्री कम हो गयी। फलतः आटो क्षेत्र में शुरू हुई कर्मचारियों का छटनी सभी क्षेत्रों में विस्तारित हो रहा है। इससे उत्पादन क्षेत्र (manufcturing sector) में वृद्धि कम हो जाने के परिणास्वरूप देश में आर्थिक मंदी का तांडव

हो रहा है। ये सब बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों का ही विश्लेषण है। लेकिन मोदी सरकार इसे टुकराते हुए कहती है कि देश में आर्थिक मंदी नहीं, सिर्फ वृद्धि दर ही धिमी (स्लो डाउन) हो गयी है। दरअसल वह चार किस्तों में आर्थिक पैकेज घोषणा करने के बावजूद उससे उबरने का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रही है।

मोदी सरकार अभूतपूर्व स्तर पर अपनी सरकारी सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों की तैनाती, कर्फ्यू-निषेदाज्ञा लगाकर हजारों लोगों को जेलों में ठूस कर जम्मू-कश्मीर राज्य की नाकेबंदी कर 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला 370 धारा एवं 35ए धारा का खत्म कर कश्मीर राष्ट्रीयता के लोगों पर फासीवादी हमला कर, उस आंदोलन को कुचलने पर उतारू है। राष्ट्रीय नागरिकता रिजिस्टर (एनआरसी) के नाम पर असम में कभी कई पीढ़ियों से पहले पलायन कर आये लाखों मुस्लिमों, बंगालियों एवं रोहिंग्या लोगों के अंदर तीव्र असुरक्षा की भावना एवं बहुतों तकलीफों में डाल दी। उसने कश्मीर की विशेष दर्जा खत्म करना, एनआरसी के नाम पर देशभर में जनता में आतंक एवं असुरक्षा में डालने के अलावा, आगामी दिनों में देश के उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं की अस्तित्व को खत्म करने के लिए सभी राष्ट्रीयताओं पर हिंदी भाषा थोपने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कालग्रस्त हिदुत्व फासीवादी दृष्टिकोण से भी नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनायी है।

इस साल फरवरी में वन्यप्राणियों के संरक्षण के नाम पर जंगलों में तीन पीढ़ियों से आवास करने की सबूत न देने वाले आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इससे देश के 16 राज्यों के 11 लाख आदिवासी जीवन-मरण समस्या का सामना किया। इसके खिलाफ देशभर में आदिवासियों ने आंदोलन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उक्त फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगाया। किंतु सुप्रीम कोर्ट का फैसला से और आगे बढ़कर केंद्रीय सरकार ने नया वन मसविदा संशोधन कानून-2019 लाया है, जिसके तहत देश में जंगली इलाकों में आवास कर रहे है 11 करोड़ से अधिक आदिवासियों सहित पीढ़ी-पीढ़ियों से जंगलों में आवास कर रहे गैरआदिवासी जन समुदायों को भी जंगलों से भगाकर, जंगलों को देश-विदेशी कार्पोरेट कंपनियों, दलाल नौकरशाह सरकारी संस्थाओं, सैन्य व अर्धसैनिक बलों को हवाला करना चाहती है। इससे जंगली इलाकों में आदिवासी एवं गैरआदिवासी

लोगों की अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गयी है।

देश में साम्राज्यवादियों, दलाल नौकरशाही पूंजीपति एवं सामंती वर्गों के शोषण एवं उत्पीड़नों को स्थायी बनाना ही ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी राज्य की स्थापना का लक्ष्य है। इसके लिए एक तरफ उत्पीड़ित वर्गों पर, उत्पीड़ित सामाजिक समुदायों पर, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं पर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमले करते हुए ही, दूसरी तरफ उन तबकों का उद्धार करने का दावा करते हुए हिंदू फासीवादी कार्पोरेट मीडिया का इस्तेमाल कर जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। इसके लिए लगातार झूठी राष्ट्रवाद एवं झूठी देशभक्ति को बहका रहे हैं। पाकिस्तान से देश को खतरा है, उग्रवादियों एवं अलगावादियों से देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, माओवादी विकास-विरोधी हैं कहते हुए जनता को धोखा दे रहे हैं। विश्व में एवं देश में आर्थिक संकट एवं जनता के कष्ट एवं तकलीफों के कारणों को जनता से छिपाकर उन्हें लड़ने से एवं क्रांति से वंचित रखकर उन्हें राष्ट्रोन्माद का शिकार बनाने की एक भारी योजना के तहत ही हिंदू फासीवादी का इस प्रचार का उद्‌देश्य है। ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादियों के साजिशों का भण्डाफोड़ कर जनता को वर्ग संघर्ष में गोलबंद करने के लिए हमें दीर्घकालीन एवं फौरी योजनाओं के साथ तैयार होना चाहिए। इसके लिए एक तरफ ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद के खिलाफ वैचारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लड़ते हुए उत्पीड़ित जनता पर उसकी फासीवादी हमलों का प्रतिरोध करने में पीएलजीए अगली पंक्ती में खड़े रहना चाहिए।

देश में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवादी व सामंती शोषण एवं उत्पीड़न को उन्मूलन कर नवजनवादी भारत का निर्माण करने के लिए, देश को हिंदू फासीवादियों से बचाने के लिए व्यापक रूप से गोलबंद होने, एकजुट-संगठित होने एवं जुझारू रूप से लड़ने तथा बड़े पैमाने पर पीएलजीए में भर्ती होने देश की जनता का सीएमसी आह्वान करता है।

प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' हमले को हराने के लिए पिछले सालभर में हमारे वीर पीएलजीए द्वारा हासिल गुरिल्ला युद्ध के सफलताओं को जनता, पार्टी के कतारों एवं पीएलजीए के योद्धाओं में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने, दिसम्बर महीने में चलाये जाने वोले भर्ती अभियान को सफल बनाने पार्टी कमेटियों एवं पीएलजीए कमांडों का सीएमसी आह्वान करता है।

☆ प्रतिक्रांतिकारी 'समाधान' हमले को साहसिक रूप से मुकाबला करें! दुश्मन का सफाया करते हुए हथियार छीन लें!

☆ दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करना गुलामी के समान है! दुश्मन के धोखेबाजी आत्मसमर्पण नीतियों को ठुकरा दें!

☆ नुकसानों से बचें! दुश्मन के हमले का परास्त करें!

☆ पार्टी, पीएलजीए और संयुक्तमोर्चा को संगठित करें!

☆ क्रांतिकारी जन सरकारों (आरपीसी) को मजबूत और विस्तारित करें!

☆ पीएलजीए में बड़े पैमाने पर युवक-युवतियों की भर्ती करें!

☆ साम्राज्यवाद-विरोधी, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद-विरोधी एवं सामंतवाद-विरोधी वर्गसंघर्ष को तेज करें!

☆ ब्राह्मणीय हिंदू फासीवाद के खिलाफ मजबूत और जुझारू आंदोलन का निर्माण करें!

☆ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद जिंदाबाद!

☆ पीएलजीए जिंदाबाद!

☆ भाकपा (माओवादी) जिंदाबाद!

☆ नवजनवादी क्रांति जिंदाबाद!

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

सेंट्रल मिलिटरि कमिशन,

3-10-2019 **भाकपा (माओवादी)**